

हिंदी में मीडिया का बदलता स्वरूप

Dr. Savita Tak

Assistant Professor, Hindi, M.L.V. Government College, Bhilwara, Rajasthan, India

सार

संचार माध्यम अथवा मीडिया का स्वरूप तेजी से इस प्रकार बदलता दिखाई दे रहा है कि इस पर काले बादल मंडराते दिखाई दे रहे हैं। अतः यह कर पाना कठिन है कि माध्यम के परोपकारी एवं कल्याणकारी महावीर स्वरूप और उद्देश्य क्या होंगे? यह स्थिति केवल हमारे देश की ही नहीं, विश्व के संपूर्ण देशों में संचार माध्यमों का यही हाल है। यह बात ऑस्ट्रिया के शहर सिल्सवर्ग में 20 से 24 मार्च 2002 तक आयोजित पत्रकारों के 396 व अधिवेशन से स्पष्ट होती है। इस अधिवेशन में भारत सहित 20 देशों के पत्रकारों तथा पत्रकार जगत से संबंधित विशेषज्ञों ने भाग लिया। इसका विषय था – विभिन्न माध्यमों की विश्वसनीयता में गिरावट, जिसके परिणाम स्वरूप माध्यमों के सामाजिक दायित्व में कमी (The decline of the news media's role as a public trust and effects of that phenomenon)

जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि पत्रकारिता का यह मूल उद्देश्य जनसाधारण को सूचना देकर संकट के समय सामाजिक दायित्व के प्रति उन्हें सजक करना है। इस अधिवेशन में हुई गंभीर चर्चा के बाद प्रतिभागियों का यह दृढ़ मत रहा कि वर्तमान में इस मूल उद्देश्य (समाचार संकलन, चयन एवं प्रकाशन) की गुणवत्ता पर विज्ञापन से होने वाली आय का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जिससे वर्तमान पत्रकारिता पर गहरा आघात हो रहा है। वह जनहित में ना होकर औद्योगिकीकरण की दिशा में अग्रसर हो रही है। वह वर्तमान में जनसंचार माध्यमों में रत संस्थान विज्ञापन द्वारा अधिक से अधिक धन कमाने में रुचि रखते हैं एवं समाचार के संकलन व प्रकाशन को उचित परिवेश में प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, लेकिन विश्व में मीडिया जगत के अधिकांश संस्थान इस मायाजाल में फँस चुके हैं।

परिचय

सामाजिक सुरक्षा एवं मानवता की स्वाधीनता के लिए मीडिया की स्वतंत्रता अनिवार्य है। सक्रिय पत्रकारिता पर ही देश की सार्वभौमिकता अवलंबित है। यह तभी संभव है जब प्रसारित समाचारों का चयन, संगम एवं प्रकाशन सही परिवेश में को। उसके गुण दोषों पर आदान प्रदान के अवसर मिलते रहे, उनका सक्रिय विश्लेषण हो। पत्रकारिता के इसी महत्व को देखते हुए अनेक देशों में उन्हें संवैधानिक एवं कानूनी सुरक्षा दी गई है। इन संरक्षणों के कारण प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नियंत्रण तथा संसरशिप इत्यादि से परे रखा गया है। जनसंचार माध्यम से संबंधित व्यक्तियों को आदर सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो 21वीं सदी के प्रारंभ से माध्यम का राजनीतिकरण एवं औद्योगिकीकरण प्रारंभ हुआ। यदि इस समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए समुचित उपाय न किए गए तो मीडिया को दी गई स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। यह देश की एकता सार्वभौमिकता एवं देश के विकास में बाधक हो सकती है। आज हर जगह मीडिया का औद्योगिकीकरण एक विकराल रूप ले चुका है। बढ़ते लाभान्श के कारण यह अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। नागरिकों के मूल अधिकारों की सुरक्षा, देश की संस्कृति एवं उसकी एकता पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। इस हानि का आकलन आज संभव नहीं। यह मूल्यांकन का विषय है। [1,2]

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात् टीवी एवं रेडियो का संचालन विज्ञापन से प्राप्त आय द्वारा ही संभव है। लेकिन आप प्रिंट मीडिया औद्योगिकीकरण की होड़ से अछूता नहीं है। विज्ञापन से होने वाली आय के परिणाम स्वरूप इन संस्थानों के मालिक भी समाचार के चयन, उनके संपादन में भी दखल देते हैं। इसका सीधा प्रभाव माध्यम की भूमिका पर पड़ रहा है। औद्योगिक ता को प्राथमिक देने की स्पर्धा में ऐसी प्रवृत्ति को जन्म दिया है कि समाचार का चटपटा स्वरूप प्रसारित हो रहा है। है उनका मूल्य उद्देश्य प्रकाशन की संख्या में वृद्धि हो गया है, ताकि विज्ञापनों की प्राप्ति में सुविधा हो सके। वर्तमान में प्रिंट मीडिया के तुलना में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे टीवी के विभिन्न चैनलों पर यह व्यावहारिक तथा उत्तेजक विज्ञापनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे जनसाधारण से उनका संपर्क टूटता जा रहा। है वह एक नई संस्कृति को पनपाने में भागीदार बन गए हैं। क्या से माध्यम पर मंडराते शनि का प्रभाव नहीं कहा जा सकता? आते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस अधिवेशन यह प्रस्ताव पारित किया गया कि विश्व में मीडिया से जुड़े संस्थानों के मालिकों से अनुरोध किया जाए कि वह मीडिया के उद्देश्य की रक्षा के लिए अपने दायित्व को समझें था इसके औद्योगिकीकरण एवं भूमिका के निर्वाह हेतु संतुलित मार्ग अपनाएं, ताकि मीडिया की सार्थकता सिद्ध हो सके और मानवता की स्वाधीनता एवं अधिकारों की रक्षा हो। विकासशील देशों पर को शनि की वक्र दृष्टि का प्रभाव स्पष्ट देखने में आता है। विकसित देशों को विकासशील देशों के बढ़ते



प्रभुत्व से खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। इसलिए पश्चिम के ये समाचार पत्र अनर्गल समाचारों के माध्यम से विकासशील देशों के विपरीत कमरकस चुके हैं। उदाहरण के तौर पर यह प्रचारित किया गया कि –

चीन में धार्मिक संगठन फालगुणगोंग से चीन के साम्यवाद प्रशासन को संकट पैदा हो गया है। जबकि साम्यवाद स्वयं धीरे-धीरे उदारवादी नीति के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। जापान के लोग कंप्यूटर के बढ़ते प्रभाव से निकम्मे एवं आलसी होते जा रहे हैं। रूस की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई है। इसके पीछे उद्देश्य जो भी हो, इससे विकासशील देशों की राजनीति एवं उसके सामाजिक ढांचे पर विपरीत असर पड़ रहा है। इसके प्रति विकासशील देशों को तत्काल सजगता बरतना आवश्यक प्रतीत होता है। भारत की स्थिति और भी गंभीर है। लगता है कि शनि की साढ़ेसाती का विकट प्रभाव उस पर पड़ा है। मीडिया के नैतिक दिशा-निर्देश के अभाव में वह समाज के बुनियादी ढांचे को तहस नहस करने, उपभोक्तावाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने एवं राजनेताओं के व्यक्तिगत जीवन की छवि को विकृत करने में लगे हैं। उदाहरण स्वरूप, भारत के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति को लड़खड़ाते हुए दिखलाना, एक मुख्यमंत्री को एक प्रभावशाली नेता के जूते उठाते हुए प्रदर्शित करना, एक प्रधानमंत्री का एक जूता पहन कर ही चल देना, एक भ्रष्टाचारी नेता के जेल से छूटने पर हाथी पर बिठाकर जुलूस निकालने तथा रसोई घर में सब्जी पकाते हुए उसकी छवि को उभारना इत्यादि ऐसे अनेक दृश्य एवं समाचार जिनका नैतिकता आधार पर निषेध होना चाहिए। क्या यह सब मीडिया या माध्यम का दायित्व है [3,4]

30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सन् 1826 में हिंदी भाषा के पहले समाचार पत्र 'उदन्त मार्तण्ड' का प्रकाशन शुरू हुआ था। कोलकाता से निकले इस साप्ताहिक समाचार पत्र ने जो प्रकाश दिखाया उसकी रौशनी में धीरे-धीरे हजारों हिंदी समाचार-पत्र शुरू हुए, पाठकों का विश्वास जीता और आगे बढ़ते रहे। यह वह समय था जब पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी और सरकार तथा जनता के बीच पुल का काम किया करती थी। समय के साथ समाचार पत्रों का ही नहीं बल्कि समाचार लेखन का भी स्वरूप बदला। समाचार और विश्लेषण निष्पक्ष से पक्षकार होते चले गये और अब तो अधिकतर समाचार पत्र के नाम से लोग पहचानते हैं कि कौन-किस पार्टी की ओर झुकाव रखता है। समाचार पत्र उठाएंगे तो विज्ञापन बड़े और खबरें छोटी नजर आयेंगी। राष्ट्रीय महत्व और जन सरोकार की खबरों से ज्यादा सनसनीखेज खबरों को महत्व दिखेगा और संपादकीय पृष्ठ की गरिमा का तो अब बहुत ही कम ख्याल देखने को मिलता है। कई समाचार पत्रों ने तो हिंग्लिश को मान्यता देकर हिंदी भाषा को गहरी ठेस भी पहुँचाई है।

इसी ढिलाई के परिणाम स्वरूप यदि विदेशी संवाददाता देश के वर्तमान प्रधानमंत्री की छवि को अक्षम, अविवेकपूर्ण एवं तर्कहीन तथा पिनक में रहने वाले की तरह तोड़ मरोड़कर प्रसारित करें अथवा देश की छवि का उल्टा रूप प्रसारित करें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। मेरा इशारा विदेशी पत्रिका 'टाइम्स' में प्रकाशित एक शरारत एवं अविवेकपूर्ण लेख, जिसका शीर्षक "A sleep at the wheels" यानी 'पहिए पर सोते हुए' के प्रकाशन से है। यह लेख पत्रिका के भारत स्थित संवाददाता एलेक्स परी ने लिखा था। उनके निष्कर्ष का आधार ना तो डॉक्टरी रिपोर्ट है, नहीं किसी विशेषज्ञ का मत उनके लिए एक के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को खाने की आदत को लेकर ऊलजलूल, आधारहीन निष्कर्ष निकाल कर प्रस्तुत किया गया। लेख का सारांश यह था कि श्री वाजपेयी खाने पीने पर नियंत्रण न रखने के कारण इस तरह बीमार, लाचार एवं अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं कि उनकी उंगली के नीचे परमाणु बम का बटन रहने पर वह कभी भी अविवेकपूर्ण स्थिति में उसे दबा सकते हैं। क्या यह एक पेशेवर विदेशी स्वस्थ पत्रकारिता का तकाजा है? ऊपर से रुतवा यह की संवाददाता अपने किए पर खेद तक प्रकट करने को तैयार नहीं। देश के ऐसे वातावरण में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 57 वर्ष के बाद समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में 26 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति देकर एक नया बवंडर खड़ा कर दिया है। प्रिंट मीडिया उद्योग के एफडीआई के समर्थन वाला मंत्रिमंडल का निर्णय तर्क की दृष्टि से एक उपयुक्त कदम है। प्रिंट मीडिया उद्योग की लागत लगभग 7000 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय पार्क पाठक सर्वेक्षण (एन. आर. एस) 2002 से पता चलता है कि वर्तमान में प्रिंट मीडिया की पाठक संख्या 10% से बढ़कर 16 से 18 करोड़ तक पहुंच चुकी है। इसमें समाचार पत्रों की पाठक संख्या लगभग 13.1 से 15.6 करोड़ हो गई है। इससे यह संकेत मिलता है कि लगभग 24.8 करोड़ ऐसी वयस्क आबादी है जो पढ़ी लिखी तो है पर कोई समाचार पत्र अथवा पत्रिका की सीमा रेखा में नहीं आती। दूसरे शब्दों में, समाचार पत्रों के अभाव अथवा आकर्षण से पढ़ी-लिखी वयस्क आबादी का योग देश के विकास में नहीं हो पा रहा है। वह देश की मुख्य धारा से अलग-थलग हैं। अभी तो यह केवल मंत्रिमंडल का निर्णय है। जिस प्रकार समाचार पत्रों के महत्व के दिशा निर्देश पर संसद में बहुमत के अभाव में वर्ष 1997 फैसला नहीं हो पाया उसी तरह ऐसे साहसिक एवं क्रांतिकारी निर्णय पर संसद से उसे कभी बहुमत प्राप्त होगा अथवा नहीं [5,6] क्योंकि विपक्षी नेताओं के विरोध का आलाप अभी से प्रारंभ कर दिया है।

महामारी के इस दौर में हमने देखा कि समाचार पत्रों की बिक्री पर काफी असर पड़ा। कोरोना जब आया तब लोग अखबार को छूने से भी डरने लगे, नतीजतन अखबार कम छपने लगे क्योंकि उनका वितरण बंद हो गया था। इसलिए समाचार पत्रों ने अपने ई-संस्करणों पर ध्यान देना शुरू किया जोकि इससे पहले तक मुफ्त में पढ़े जा सकते थे अब उन पर शुल्क लगा दिया गया। एक बड़े समाचार पत्र ने तो अदालत से आदेश भी हासिल कर लिया कि उनके ई-संस्करणों को सोशल मीडिया पर शेयर या फॉरवर्ड

नहीं किया जाये जिसे पढ़ना है वह शुल्क देकर पढ़े। हिंदी समाचार पत्रों की यात्रा भले बेहद उतार-चढ़ाव वाली रही हो लेकिन यह कहा जा सकता है कि आज भी सत्य खबर के लिए समाचार पत्रों पर विश्वास कम नहीं हुआ है।

विचार-विमर्श

विगत दो दशकों में मीडिया के स्वरूप में बहुत तेज़ बदलाव देखने को मिला है। सूचना क्रांति एवं तकनीकी विस्तार के चलते मीडिया की पहुँच व्यापक हुई है। इसके समानांतर भूमंडलीकरण, उदारीकरण एवं बाज़ारीकरण की प्रक्रिया भी तेज़ हुई है, जिससे मीडिया अछूता नहीं है। नए-नए चैनल खुल रहे हैं, नए-नए अखबार एवं पत्रिकाएँ निकाली जा रही हैं और उनके स्थानीय एवं भाषायी संस्करणों में भी विस्तार हो रहा है। मीडिया के इस विस्तार के साथ चिंतनीय पहलू यह जुड़ गया है कि यह सामाजिक सरोकारों से दूर होता जा रहा है। मीडिया के इस बदले रुख से उन पत्रकारों की चिंता बढ़ती जा रही है, जो यह मानते हैं कि मीडिया के मूल में सामाजिक सरोकार होना चाहिए। मीडिया की प्राथमिकताओं में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, विस्थापन जैसे मुद्दे रह ही नहीं गए हैं। उत्पादक, उत्पाद और उपभोक्ता के इस दौर में खबरों को भी उत्पाद बना दिया गया है, यानी जो बिक सकेगा, वही खबर है। दुर्भाग्य की बात यह है कि बिकाऊ खबरें भी इतनी सड़ी हुई हैं कि उसका वास्तविक खरीददार कोई है भी या नहीं, पता करने की कोशिश नहीं की जा रही है। बिना किसी विकल्प के उन तथाकथित बिकाऊ खबरों को खरीदने (देखने, सुनने, पढ़ने) के लिए लक्ष्य समूह को मजबूर किया जा रहा है। खबरों के उत्पादकों के पास इस बात का भी तर्क है कि यदि उनकी "बिकाऊ" खबरों में दम नहीं होता, तो चैनलों की टी.आर.पी. एवं अखबारों की रीडरशिप कैसे बढ़ती? इस बात में कोई दम नहीं है कि मीडिया का यह बदला हुआ स्वरूप ही लोगों को स्वीकार है, क्योंकि विकल्पों को खत्म करके पाठकों, दर्शकों एवं श्रोताओं को ऐसी खबरों को पढ़ने, देखने एवं सुनने के लिए बाध्य किया जा रहा है। उन्हें सामाजिक मुद्दों से दूर किया जा रहा है। यह बात ध्यान देने की है कि भारत जैसे विकासशील देश में मीडिया की भूमिका विकास एवं सामाजिक मुद्दों से अलग हटकर नहीं हो सकती। हमारी अपनी सामाजिक समस्याएँ हैं, विषमताएँ हैं और सिस्टम की कमियाँ हैं, कानून व्यवस्था खामियाँ हैं। ऐसे में क्या मीडिया महज एक तमाशबीन बनकर रह सकता है? क्या वह सत्ता और कॉर्पोरेट जगत का पिछलग्गू मात्र बना रह सकता है? शायद नहीं! इससे न केवल समाज के स्वस्थ मूल्यों को ही खतरा है बल्कि स्वयं मीडिया के अस्तित्व को भी है। ऐसे समय में सुप्रसिद्ध पत्रकार प्रमोद भार्गव की पुस्तक "मीडिया का बदलता स्वरूप" हमें कुछ सुकून देती है। इस पुस्तक में पत्रकारिता के सन्दर्भ में लिखे गए ऐसे लेख सम्मिलित हैं जो इस देश के जनमानस और उसकी अपेक्षाओं के बारे में अपनी चिंता से हमें अवगत कराते हैं। इसमें लेखक एक ओर अपनी सनातन सांस्कृतिक पहचान की दृष्टि से घटित घटनाओं और समाचारों का विश्लेषण करता है तो वहीं बहुलतावादी समृद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण पक्षों पर भी अपने विचार रखता है। खोजी विज्ञान पत्रकारिता के बारे में लेखक कहता है- "विज्ञान के क्षेत्र में खोजी पत्रकारिता लगभग नगण्य है, परन्तु स्वस्थ विज्ञान पत्रकारिता के लिए आज इसकी ज़रूरत है। आमतौर पर विज्ञान पत्रिकाओं के अधिकांश लेखक वैज्ञानिक होते हैं और वे विज्ञान से रोज़गार के रूप में जुड़े हुए हैं।" ज़ाहिर है वे एक जानकारी वाला पक्ष उजागर करते हैं उसकी सामाजिक उपयोगिता के आगे उसके सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव तथा सोच में प्रयोगात्मक व रचनात्मक विकास की ओर उनका ध्यान नहीं जाता, [7,8] पत्रकारिता वाली खोजी दृष्टि वहाँ नहीं होती। विज्ञान की स्थूल समझ के आगे एक वैज्ञानिक समझ का विकास भी होता है जो समाजवैज्ञानिक पहलू है। इस दृष्टि से भी इस विषय को देखना चाहिए। जहाँ पत्रकारिता भी पीछे रह जाती है। पेड न्यूज़ को लेकर लेखक कहता है कि - "पेड न्यूज़, नकदी अथवा उपहार लेकर समाचार छापने की घटना है जो अनैतिक और बेमेल व्यवसायिक गठबंधनों की देन है।" लेखक यह भी इंगित करता है कि समाचार माध्यमों को सरकारी-गैरसरकारी विज्ञापनों के मार्फ़त जो पैसा मिलता है अंततः वह जनता की ही गाढ़ी कमाई का पैसा होता है इसलिए प्रत्येक नागरिक को यह जानने का है कि मीडिया क्या खेल रहा है। लेखक का मत है कि पेड न्यूज़ के बहाने किये जाने वाले भ्रष्टाचार को अपराध के दायरे में लाया जाना चाहिए। स्टिंग ऑपरेशनों के बहाने टी आर पी बढ़ाने की प्रवृत्ति बिकने की प्रवृत्ति ही है। आसाम के एक न्यूज़ चैनल के मालिक ने एक महिला के साथ हुई छेड़छाड़ की निंदनीय घटना को टी आर पी बढ़ाने के लिए शह देकर खबर के तौर पर प्रायोजित किया था। क्या यह मीडिया के अपराधीकरण को नहीं दर्शाता है? [9] आगे सवाल यह उठता है कि क्या बाज़ार की गोद में बैठ कर ई पत्रकारिता सच की वाहक बन पाएगी। लेखक के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जवाबदेही को इस हद तक नज़रअंदाज़ किया जाने लगा है कि खबरें उत्सर्जित की जाने लगी हैं। यह स्थिति राष्ट्र, समाज और खबर के चरित्र के साथ खिलवाड़ है। हिंदी व क्षेत्रीय प्रिंट मीडिया के बारे में लेखक का मानना है कि जैसे-जैसे इन अखबारों के संस्करण, प्रसार संख्या और पाठक संख्या में वृद्धि हो रही है वैसे-वैसे इनके पत्रे अंग्रेज़ी अखबारों के अनुवादों से भरे जाने लगे हैं। चिंता का विषय यह भी है कि मीडिया का एक हिस्सा न केवल अंधविश्वास से जुड़े विज्ञापन लगातार प्रचारित प्रसारित करता है बल्कि उनके ऊपर अपने खास कार्यक्रम भी चलाता है। अखबार उनपर परशिए छापते हैं। अवैज्ञानिक, अतार्किक, अलौकिक एवं सचाई से परे अतीन्द्रिय शक्तियों का भ्रम कुछ समाचार व धार्मिक चैनल फैलाते हैं जो समाज में नकारात्मकता, अन्धविश्वास व अपराध का कारण बन रहा है। एक सभ्य समाज में यह प्रवृत्ति नितांत अनावश्यक है। विकीलीक्स द्वारा उजागर की वाली गोपनीय वैश्विक सूचनाएँ इस समय बौद्धिक समाज द्वारा स्वागत के योग्य मानी जा रही हैं। जिसने अमेरिका जैसे देशों की चौधराहट को भी चुनौती दे डाली है। बाज़ारवाद के दौर में एंग्लिट पोल का धंधा भी खूब फलफूल रहा है जो सियासी अनैतिक हथकंडों को पनाह दे रहा है। इस तरह इस पुस्तक में सूचना से जुड़े हर पक्ष पर लेखक ने मुखर होकर अपने विचार रखे हैं। एक सजग पत्रकार होने के नाते प्रमोद भार्गव की ये चिंताएँ न केवल उचित हैं बल्कि मीडिया के परिष्कार की उनकी अभिलाषा को भी सामने रखती हैं। हमारे देश के मीडिया में सजग,

संवेदनशील और चिंतनशील पत्रकारों एवं मीडियाकर्मियों की एक बड़ी संख्या है जो इस स्थिति से कदापि संतुष्ट नहीं हैं। वे इन स्थितियों में सकारात्मक और रचनात्मक बदलाव के पक्षधर हैं। कुछ हद तक सोशल मीडिया और वैकल्पिक प्रिंट मीडिया इसकी भरपाई कर भी रहे हैं। लेकिन मुख्यधारा के मीडिया में इसकी शुरुआत होनी अपेक्षित है जो बेहद ज़रूरी भी है। 90 के दशक में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तेजी से उभर रहा था तो हिंदी पत्रकारिता को एक नयी दिशा मिली। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने टीवी का रुख किया और कुछ ने पश्चिम की शैली का अनुसरण किया तो कुछ ने अपनी नयी शैली विकसित करते हुए टीवी पर हिंदी भाषा में खबरों को प्रस्तुत कर नया मंच खड़ा कर दिया। यह मंच ऐसा था जिसने हजारों की संख्या में रोजगार दिये और एक बड़े उद्योग का रूप लेकर हजारों करोड़ रुपये कमाये भी। लेकिन धीरे-धीरे टीवी समाचारों पर व्यावसायिकता हावी होने लगी और समाचार चैनल 'इशारों पर' एजेंडा सेट करके चलाने लगे। आज स्थिति ऐसी है कि चाहे कोई सबसे तेज खबर देने वाला चैनल हो या सबसे ज्यादा खबर देने वाला चैनल सभी किसी ना किसी की ओर झुकाव रखते ही हैं।[9]

परिणाम

हिन्दी शब्द 'माध्यम' से अंग्रेजी में 'मीडियम' और मीडिया बना। एक जगह की बात या घटना को दूसरी जगह पहुंचाने में जो व्यक्ति या उपकरण माध्यम बनता है, वही मीडिया है। सृष्टि के जन्मकाल से ही किसी न किसी रूप में मीडिया का अस्तित्व रहा है और आगे भी रहेगा। इस सृष्टि में नारद जी पहले पत्रकार हैं। इसीलिए उनकी जयंती (ज्येष्ठ कृष्ण 2) वास्तविक 'पत्रकारिता दिवस' है। 30 मई को देश भर में 'हिन्दी पत्रकारिता दिवस' मनाया जाता है। चूंकि 1826 में इस दिन श्री जुगल किशोर शुक्ल ने कोलकाता से हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार 'उदन्त मार्त्तण्ड' शुरू किया था। उस दिन नारद जयंती ही थी। यद्यपि अर्थाभाव में यह 11 दिसम्बर 1827 को बंद हो गया; पर पत्रकारिता के इतिहास में नारद जयंती को पुनर्जीवित कर गया। कहते हैं कि नारद जी की पहुंच देव, गंधर्व, नाग आदि लोकों से लेकर आकाश और पाताल तक थी। वे अपनी वीणा लेकर 'नारायण-नारायण' करते हुए हर उस जगह पहुंच जाते थे, जहां उनकी जरूरत होती थी। दुर्भाग्य से हमारी फिल्मों और दूरदर्शन ने उनकी छवि एक जोकर और यहां-वहां आग लगाने वाले व्यक्ति की बनायी है। जबकि वे लोकहितकारी पत्रकार थे। उनके सामने जनता का हित सर्वोपरि रहता था। श्रीकृष्ण के जन्म का ही उदाहरण लें। अपनी बहिन देवकी को ससुराल छोड़ने जाते समय हुई भविष्यवाणी से चिंतित होकर कंस ने देवकी ओर वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। इसके बाद वह देवकी की आठवीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। नारद जी जानते थे कि जब तक कंस के पाप का घड़ा नहीं भरेगा, तब तक जनता में विद्रोह नहीं होगा। इसलिए वे आठ पंखुड़ी वाला कमल लेकर कंस के पास गये और उसकी आठवीं पंखुड़ी पहचानने को कहा। इससे कंस भ्रमित हो गया। उसने अपनी दुष्ट मंडली से पूछा, तो सबने देवकी के सभी बच्चों को मारने की सलाह दी। कंस ने ऐसा ही किया। लेकिन इससे लोगों में आक्रोश बढ़ता गया और सबने तय कर लिया कि चाहे जो हो, पर आठवीं संतान को बचाना ही है। इसलिए श्रीकृष्ण के जन्म लेते ही जेल के पहरेदार, लुहार आदि ने उनके निकलने का प्रबंध कर दिया। नाव वालों ने ऐसी मजबूत नाव बनायी, जो दूर से शेषनाग जैसी दिखती थी और उससे श्रीकृष्ण को उफनती यमुना पार करा दी गयी। फिर इसी तरह गोकुल से देवकी की नवजात कन्या को ले भी आये।[6,7] इसके बाद कंस को सूचना दी गयी। यह कथा नारद जी की बुद्धिमत्ता और योजना को बताती है। कोई कह सकता है कि नारद जी हर युग और काल में कैसे हो सकते हैं? वस्तुतः नारद जी कोई व्यक्ति न होकर एक संस्था या उसके पदाधिकारी थे, जैसे आजकल प्राचार्य, अध्यक्ष या मुख्यमंत्री आदि होते हैं। इसलिए नारद जी आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। सत् और त्रेता के बाद द्वापर युग आता है। तब विज्ञान बहुत उन्नत था। इसीलिए कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत का आंखों देखा हाल संजय ने हस्तिनापुर में बैठे धृतराष्ट्र को सुनाया था। अर्थात् तब भी दूरदर्शन जैसा कोई उपकरण अवश्य रहा होगा। महाभारत के युद्ध में विज्ञान की समृद्धि प्रगति दांव पर लग गयी थी। इससे विश्व की अधिकांश जनसंख्या और विज्ञान भी नष्ट हो गया। लेकिन मीडिया की जरूरत फिर भी बनी रही। कभी कबूतर, घोड़े या ऊंट सवारों से संदेशवाहकों का काम लिया जाता था। पर्वत और वनों में ढोल की थाप से संदेश पहुंचाए जाते थे। 'ढोल सागर' नामक ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है, यद्यपि अब उसका बहुत कम भाग ही उपलब्ध है। अंग्रेजों ने भारत में 1850 में टेलिफोन की तारें लगायीं। इससे कहीं भी हुए सैन्य विद्रोह की सूचना तुरंत देश भर में पहुंच जाती थी। 1857 में कोलकाता की बैरकपुर छावनी और फिर कुछ दिन बाद मेरठ छावनी में विद्रोह हुआ। टेलिफोन से इसकी सूचना सब छावनियों में पहुंच गयी और वहां कार्यरत भारतीय सैनिकों से हथियार ले लिये गये। यह कमाल टेलिफोन का ही था। इसीलिए भारतीय स्वाधीनता सेनानी हर जगह सबसे पहले टेलिफोन की तारें काटते थे। इन तारों से टेलिग्राम भी होते थे। 1854 में इसकी व्यावसायिक सेवाएं शुरू हुईं। 1902 में ये वायरलेस हो गया; पर एक समय पत्रकार इसी से समाचार अखबारों को भेजते थे। पुरानी पड़ जाने से 2013 में यह सेवा बंद कर दी गयी। इसी में से फिर टेलिप्रिंटर का जन्म हुआ, जो अखबारों के लिए अनिवार्य चीज थी। हर समाचार एजेंसी के अपने टेलिप्रिंटर होते थे। पहले केवल अंग्रेजी टेलिप्रिंटर ही थे; पर फिर हिन्दुस्थान समाचार ने हिन्दी टेलिप्रिंटर बना लिया। इसके बाद फैक्स मशीन आ गयी। कम्प्यूटर, मोबाइल और ई.मेल के दौर में अब वह भी पुरानी हो गयी है। एक समय केवल प्रिंट मीडिया ही था; पर फिर टी.वी. आ गया। चूंकि दृश्य सदा लिखित सामग्री से अधिक प्रभावी होता है। कबीर दास जी ने भी 'आंखों देखी' को 'कागद की लेखी' से अधिक महत्व दिया है। अब घर के टी.वी. से आगे मोबाइल टी.वी. और सोशल मीडिया आ गया है। इसके आगे क्या होगा, कहना कठिन है। हो सकता है पोलियो की तरह बच्चों को मीडिया का भी टीका लगा दिया जाएगा। फिर न टी.वी. की जरूरत होगी और न मोबाइल या इंटरनेट की। विज्ञान जो न कराए वह

थोड़ा ही है। कहते हैं कि विज्ञान का हर नया उपकरण पुराने को बाहर कर देता है; लेकिन इसके बावजूद एक चीज कभी बाहर नहीं हुई और होगी भी नहीं। वह है पत्रकार। क्योंकि मशीन कितनी भी उन्नत हो जाए; पर उसे चलाता आदमी ही है। इसलिए पत्रकार का ठीक रहना जरूरी है। [4,5] उसकी वैचारिक प्रतिबद्धता चाहे जो हो; पर समाचार के साथ विचार का घालमेल ठीक नहीं है। एक ही सभा की रिपोर्ट करते समय एक संवाददाता फोटो में खाली कुर्सियों वाला क्षेत्र दिखाता है, तो दूसरा भरी हुई। कई संवाददाता किसी से सुनकर समाचार छाप देते हैं या जानबूझ कर विवाद खड़ा कर देते हैं। इससे पत्रकार और अखबार दोनों की छवि खराब होती है। इससे बचना ही उचित है। चूंकि विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज है। किसी समय पत्रकारिता का अर्थ समाचार संकलन ही होता था; पर अब खेल, सिनेमा, फोटो, साहित्य, थाना, कोर्ट, राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं के लिए भी अलग-अलग संवाददाता होते हैं। विधा चाहे जो हो, पर पत्रकार के लिए खूब पढ़ना और भाषा पर अधिकार जरूरी है। गलत तथ्य देना अपराध ही नहीं, पाप भी है। ऐसा कहते हैं कि किसी समय मीडिया मिशन था; पर अन्य क्षेत्रों की तरह यहां भी गिरावट आयी है। अतः वह कमीशन से होते हुए सेंसेशन तक पहुंच गया है; लेकिन हजारों पत्रकार आज भी निष्ठा से काम कर रहे हैं। इसीलिए बदलते समय के साथ मीडिया का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। बात डिजिटल मीडिया की करें तो यह सही है कि यह सबसे बाद में आया लेकिन सबसे पहले आये समाचार पत्र, उसके बाद आये टीवी चैनल भी डिजिटल मीडिया मंच पर उपस्थित होने को मजबूर हुए क्योंकि यही वह माध्यम है जो बिजली की गति से दौड़ता हुआ समाचारों को पल भर में दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकता है। डिजिटल मीडिया पर प्रकाशित समाचारों को संकलित करने के लिए उन्हें फाइलों में लगा कर रखने या उनकी वीडियो क्लिप संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंटरनेट के विशाल संसार में कुछ भी, कभी भी और कहीं भी खोजा जा सकता है और उसको आगे भेजा जा सकता है। साथ ही डिजिटल मीडिया कमाई का एक बड़ा जरिया भी बन गया तो बहुत से लोग इस क्षेत्र में आ गये। डिजिटल मीडिया का क्षेत्र आज बहुत व्यापक हो गया है लेकिन अगर विश्वसनीयता के पैमाने पर आंका जाये तो डिजिटल मीडिया पर ही सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। इसलिए जरूरी हो जाता है उसका जिक्र जिसने इस मंच पर शुरुआती दौर में तो कदम रखा ही साथ ही समय के साथ पाठकों के हित में नित नये प्रयोग करते हुए बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस मंच का मार्गदर्शन भी किया। [2,3]

निष्कर्ष

डिजिटल मीडिया पर खासकर हिंदी पत्रकारिता की यदि बात की जाये तो इसे शुरू से ही विश्वसनीय मंच बनाये रखने, सही मार्ग पर बने रहने के लिए प्रेरित करते रहने और राष्ट्र प्रथम की भावना को लेकर आगे बढ़ने के साथ ही डिजिटल डिवाइड को खत्म करने में यदि किसी की महती भूमिका रही है तो वह नाम है प्रभासाक्षी। हिंदी पत्रकारिता का आरम्भ जिस मिशन के साथ हुआ था यदि उस मिशन की सच्ची भावना को डिजिटल मीडिया में कोई कायम रखे हुए है तो वह नाम है प्रभासाक्षी।

सन 2001 से अपनी यात्रा शुरू करने वाला भारत का पहला पूर्णरूपेण हिंदी समाचार पोर्टल प्रभासाक्षी ही था क्योंकि उस समय जागरण, नयी दुनिया या कुछ अन्य समाचार पत्रों की हिंदी वेबसाइट दरअसल उन समाचार पत्रों का ही ऑनलाइन संस्करण थीं जबकि प्रभासाक्षी किसी का संस्करण नहीं बल्कि पाठकों के लिए पूर्ण सूचना संसार की भाँति आया। प्रभासाक्षी हिंदी भाषा में पाठकों को ना सिर्फ समाचार बल्कि विश्लेषण, कहानी, व्यंग्य, फैशन, पर्यटन, कैरियर आदि क्षेत्रों की हर वो जानकारी दे रहा था जोकि उन्हें चाहिए थी। यही कारण है कि 2001 से लेकर अब तक के वर्षों में बहुत से हिंदी समाचार पोर्टल आये और गये, कई बड़े अंग्रेजी समाचार पोर्टलों ने अपना हिंदी पेज भी शुरू किया लेकिन या तो वह अपडेट नहीं होते थे या फिर पाठकों का विश्वास नहीं जीत पाये और जल्द ही बंद हो गये। लेकिन प्रभासाक्षी अपनी निर्बाध यात्रा के दौरान पुराने पाठकों का विश्वास बहाल रखने के साथ ही आज के युवा पाठकों का भी चहेता समाचार पोर्टल बना हुआ है। डिजिटल मीडिया पर कभी हिंदी पत्रकारिता का इतिहास लिखा जायेगा तो निश्चित ही प्रभासाक्षी का उसमें अहम स्थान होगा। क्योंकि प्रभासाक्षी डिजिटल मीडिया पर एक बड़े संसार का रूप ले चुका है। अपनी दो दशक की यात्रा पूरी करने जा रहा यह समाचार पोर्टल कई ऐतिहासिक क्षणों का गवाह रहा है और उनसे संबंधित समाचार, विश्लेषण, विशेष आलेख आज भी इस मंच पर उपलब्ध हैं। इन दो दशकों में भारत में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक बदलावों का लंबा सिलसिला चला, यही नहीं अटल बिहारी वाजपेयी, डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी की कामकाज की विशिष्ट शैली भी लोगों ने देखी समझी, यह सब इतिहास प्रभासाक्षी पर जस का तस उपलब्ध है। प्रभासाक्षी हिंदी का एकमात्र समाचार पोर्टल है जहाँ पर राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर घटित काल-विभाजक घटनाक्रमों का बड़ा संकलन मौजूद है। बात सिर्फ दो दशकों के घटनाक्रमों की ही नहीं है। आजादी के आंदोलन से लेकर आपातकाल तक के सभी घटनाक्रमों, आर्थिक उदारीकरण के शुरू हुए दौर से लेकर आत्मनिर्भरता की राह पर बढ़े भारत के हर कदम का ब्यौरा और विश्लेषण भी यहाँ मौजूद है। कहा जा सकता है कि प्रभासाक्षी ने पत्रकारिता के मूल उद्देश्यों को तो सच्ची भावना से आगे बढ़ाया ही साथ ही डिजिटल डिवाइड को खत्म करने में जो अहम भूमिका निभाई है वह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में भले स्मार्टफोन हाल के वर्षों में पहुँचे हों लेकिन इंटरनेट तो पहले से ही था और प्रभासाक्षी के माध्यम से उन्हें हर वह जानकारी मिलती रही जोकि उनके लिए जानना बेहद जरूरी था। समय-समय पर प्रभासाक्षी की खबरों ने जो असर दिखाया वह डिजिटल मीडिया माध्यम की ताकत को भी दर्शाता है। बहरहाल, डिजिटल मीडिया, खासकर इस मंच पर हिंदी पत्रकारिता का भविष्य बहुत उज्वल है लेकिन सबसे जरूरी तत्व विश्वसनीयता और निष्पक्षता को बनाये रखना होगा। सरकारों को भी इस क्षेत्र को और आर्थिक मदद देनी चाहिए क्योंकि हिंदी



राष्ट्र की भाषा होने, राजभाषा होने और सर्वाधिक लोगों की भाषा होने के बावजूद आर्थिक दृष्टि से आज भी लाभ अर्जित करने वाली भाषा नहीं मानी जाती। सरकारी और निजी प्रोत्साहन बढ़ाया जाये तो यह क्षेत्र रोजगार के बहुसंख्य अवसर प्रदान कर सकता है।[9]

संदर्भ

1. The rise and rise of Hindi: How India's most spoken language is finding new takers
2. ↑ More paid subscribers, increase in Hindi content: Inside India's OTT market
3. ↑ Looking back: How liberalisation shaped the Hindi press
4. ↑ Hindi might not be the national language – but it is growing rapidly across India
5. ↑ विज्ञापनों में हिन्दी (विश्वबन्धु)
6. ↑ <https://navbharattimes.indiatimes.com/india/unesco-has-decided-to-release-the-hindi-description-of-indian-world-heritage-sites-on-the-website/articleshow/88838273.cms> यूनेस्को ने भारतीय विश्व धरोहर स्थलों का हिन्दी विवरण वेबसाइट पर जारी करने का निर्णय लिया]
7. ↑ भारतीय भाषाओं के प्रचार-प्रसार में रेलवे की भूमिका
8. ↑ दक्षिण में भी हो रहा है हिन्दी का विस्तार
9. ↑ Koo बन रहा नम्बर 1 हिंदी माइक्रोब्लॉगिंग प्लैटफॉर्म, कुल 1 करोड़ यूजर्स में से आधे कर रहे हिंदी में बात